Governments buy goods and services to support their internal operations; they do not transform the goods and services or resell them to make a profit. Government markets usually buy their goods through a bidding process and include federal, state, county, and local governments.

सरकारें अपने आंतरिक कार्यों का समर्थन करने के लिए सामान और सेवाएँ खरीदती हैं; वे वस्तुओं और सेवाओं को परिवर्तित नहीं करते हैं या लाभ कमाने के लिए उन्हें फिर से बेचना नहीं करते हैं। सरकारी बाजार आमतौर पर बोली प्रक्रिया के माध्यम से अपना माल खरीदते हैं और इसमें संघीय, राज्य, काउंटी और स्थानीय सरकारें शामिल होती हैं।

सरकार त्यांच्या अंतर्गत कामकाजास समर्थन देण्यासाठी वस्तू आणि सेवा खरेदी करतात; ते वस्तू आणि सेवांमध्ये बदल घडवून आणत नाहीत किंवा नफा कमविण्यासाठी त्यांना पुन्हा विक्री करीत नाहीत. सरकारी बाजारपेठा सहसा बोली प्रक्रियाद्वारे त्यांचा माल खरेदी करतात आणि त्यात फेडरल, स्टेट, काउन्टी आणि स्थानिक सरकार समाविष्ट असतात.

the government market offers large opportunities for many companies, both big and small. In most countries, government organizations are major buyers of goods and services Government organizations typically require suppliers to submit bids and normally they award the contract to the lowest bidder. In some case, the government unit will make allowance for the supplier's superior quality or reputation for completing contracts on time. Government will also buy on negotiated contract basis, primarily in the case of complex projects involving major R&D costs and risks and in cases where there is little competition. Government organizations tend to favor domestic supplier. A major complaint of multinationals operating in Europe was that each country showed favoritism towards its nationals in spite of superior offers available from foreign firms. Government organizations require considerable paperwork from suppliers, who often complain about excessive paperwork, bureaucracy, regulations, decision making delays, and frequent shifts in procurement personnel.

सरकारी बाजार कई कंपनियों के लिए बड़े और छोटे दोनों तरह के अवसर प्रदान करता है। ज्यादातर देशों में, सरकारी संगठन वस्तुओं और सेवाओं के प्रमुख खरीदार हैं। सरकारी संगठनों को आमतौर पर आपूर्तिकर्ताओं को बोलियां जमा करने की आवश्यकता होती है और आमतौर पर वे अनुबंध को सबसे कम बोली लगाने वाले को देते हैं। कुछ मामलों में, सरकार इकाई समय पर अनुबंध पूरा करने के लिए आपूर्तिकर्ता की बेहतर गुणवत्ता या प्रतिष्ठा के लिए भत्ता बनाएगी। सरकार अनुबंधित अनुबंध के आधार पर भी खरीदेगी, मुख्य रूप से जटिल

परियोजनाओं में प्रमुख अनुसंधान एवं विकास लागत और जोखिम और ऐसे मामलों में जहां कम प्रतिस्पर्धा है। सरकारी संगठन घरेलू आपूर्तिकर्ता का पक्ष लेते हैं। यूरोप में काम कर रहे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की एक बड़ी शिकायत यह थी कि प्रत्येक देश ने विदेशी कंपनियों के लिए उपलब्ध बेहतर प्रस्तावों के बावजूद अपने नागरिकों के प्रति पक्षपात दिखाया। सरकारी संगठनों को आपूर्तिकर्ताओं से काफी कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होती है, जो अक्सर अत्यधिक कागजी कार्रवाई, नौकरशाही, नियमों, निर्णय लेने में देरी और खरीद कर्मियों में अक्सर बदलाव के बारे में शिकायत करते हैं।

सरकारी बाजारपेठ मोठ्या आणि लहान अशा अनेक कंपन्यांना मोठ्या संधी देते. बर्याच देशांमध्ये, सरकारी संस्था वस्तू व सेवांचे मोठे खरेदीदार असतात सरकारी संस्थांना सामान्यत: पुरवठा करणा .्यांना बिड सादर करणे आवश्यक असते आणि सामान्यपणे ते कंत्राट सर्वात कमी बोलीदात्यास देतात. काही प्रकरणांमध्ये, शासकीय युनिट पुरवठादाराच्या उत्कृष्ट गुणवत्तेसाठी किंवा करारांवर वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी प्रतिष्ठा भत्ता देईल. मुख्यतः आर अँड डी खर्च आणि जोखीम असलेल्या जटिल प्रकल्पांच्या बाबतीत आणि ज्यात कमी स्पर्धा होत असतील अशा प्रकरणांमध्येही सरकार वाटाघाटी करारानुसार खरेदी करेल. सरकारी संस्था घरगुती पुरवठादाराची बाजू घेतात. युरोपमध्ये काम करणा mult्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मोठी तक्रार अशी होती की परदेशी कंपन्यांकडून उपलब्ध असलेल्या चांगल्या ऑफर्स असूनही प्रत्येक देशाने आपल्या नागरिकांबद्दल अनुकूलता दर्शविली. शासकीय संस्थांना पुरवठा करणा from्यांकडून कागदी कागदपत्रांची आवश्यकता असते, ज्यांना बहुतेकदा जास्त कागदपत्रे, नोकरशाही, नियम, निर्णय घेण्यास विलंब आणि खरेदी कर्मचार्यांत वारंवार बदल याबद्दल तक्रार असते.

==========kg==========